भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1454

(दिनांक 12.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1454. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा तेलंगाना राज्य में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करते समय निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय को उक्त योजनाओं को लागू करते समय कोई कमियां मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय ने इन कमियों को किस प्रकार दूर किया;

(ङ) क्या उपरोक्त योजनाओं में से किसी में समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए 2019-20 में योजना स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन किया है। केंद्रीय क्षेत्र की 14 स्कीमों के युक्तिकरण के बाद, मंत्रालय अब केंद्रीय क्षेत्र की चार स्कीमें लागू कर रहा है। मंत्रालय की इन स्कीमों का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के साथ-साथ मनोरंजन और शिक्षा का व्यापक सम्प्रेषण और सूचना का प्रचार-प्रसार करना है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का लाभ तेलंगाना सहित देश की पूरी आबादी को समान रूप से प्राप्त होता है।

सूचना क्षेत्र में, विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी) स्कीम का उद्देश्य सरकार के विभिन्न योजना कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि जन कल्याण राष्ट्रीय एकता का संवर्धन और राष्ट्र निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इसे विभिन्न मीडिया साधनों यथा प्रिंट विज्ञापन, ऑडियो-विजुअल प्रचार, बाह्य प्रचार, सूचनाप्रद ब्रोशर/फ्लायर्स के वितरण, प्रदर्शनियों के दौरान पारस्परिक संवाद और नए मीडिया साधनों का उपयोग कर एकीकृत विकास संचार अभियानों के शुभारंभ के माध्यम से किया जाता है ताकि प्रभावी और लक्षित पहुंच बनाई जा सके।

फिल्म क्षेत्र में, फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के माध्यम से फिल्म समारोहों, फिल्म बाजारों, फिल्मों के निर्माण और अभिलेखीय फिल्मों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना है। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को बड़े और बहुमुखी दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी और आयोजन में विभिन्न मीडिया यूनिटों के कार्यकलापों को समन्वित करना है।

प्रसारण क्षेत्र में, प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम का उद्देश्य समय-समय पर दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रसारण अवसंरचना और सामग्री को सुदृढ़ करना है। यह लोक प्रसारक को ट्रांसमीटरों का संवर्धन और प्रतिस्थापन, सैटेलाइट प्रसारण उपकरण और डिजिटलीकरण, टीवी चैनलों के विस्तार, एफएम विस्तार के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देने के लिए व्यय की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम करेगा।

दूरदर्शन हैदराबाद में एक दूरदर्शन केंद्र (डीडी यादागिरी, सैटेलाइट चैनल) और वारंगल में 01 पीजीएफ केंद्र के साथ पूरे तेलंगाना राज्य को कवर करता है। आकाशवाणी का कवरेज भी 01 मीडियम वेव ट्रांसमीटर और 16 एफएम स्टेशनों के साथ पूरे राज्य में है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन की अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर 15.29 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

इसी प्रकार, प्रसारण क्षेत्र के तहत सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन स्कीम का उद्देश्य नए और मौजूदा सीआर स्टेशनों को संसाधनों, क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ सुदृढ़ करना है जिससे प्रचालनरत सीआरएस की संख्या और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, जो सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक है। "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन" स्कीम अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसे अवसंरचना के निर्माण के लिए पात्र मौजूदा और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को जारी किया जाता है। भारत में ऐसे विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के लिए इन निधियों का उपयोग किया जाता है जहां सामुदायिक रेडियो की पहुंच सीमित है।

वर्तमान में तेलंगाना राज्य में 9 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं।

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किसी भी स्कीम में कोई कमी नहीं है तथा समय और लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

****